



## गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन दर और ड्रॉप आउट की समस्या

**Dr. Satish Chandra Yadav**

Assistant Professor, Jasidih B.Ed College, Deoghar, Jharkhand, 814142

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.19099567>

### ARTICLE DETAILS

**Research Paper**

**Accepted:** 19-02-2026

**Published:** 10-03-2026

### Keywords:

आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक रुकावटें, टेक्नोलॉजी की कमी, री-एनरोलमेंट के मौकों

### ABSTRACT

बच्चों का स्कूलों में एडमिशन न होने की लगातार समस्या एक गंभीर सामाजिक और एजुकेशनल मुद्दा बन गई है। इसकी कई वजहें हैं, जैसे आर्थिक असमानता, गाजीपुर ज़िले जैसे ग्रामीण इलाकों में बेसिक चीज़ों तक सीमित पहुँच, बाल मज़दूरी और कम उम्र में शादी जैसी सांस्कृतिक रुकावटें, स्कूल मैनेजमेंट के अलग-अलग तरीके, बंद/अनदेखी वाली सांस्कृतिक रुकावटें, टेक्नोलॉजी की कमी, और लोकल गवर्नेंस की कमियाँ। इन वजहों से स्कूल छोड़ने की दर बढ़ गई है और एडमिशन में काफी कमी आई है। यह पेपर गाजीपुर में प्राइमरी लेवल पर स्कूलों के नाम रखने के पीछे की असली तस्वीरों, डेटा, वजहों, समाज पर उनके असर, साथ ही सरकारी कोशिशों और पॉलिसी की भूमिका का गहराई से एनालिसिस करता है। जिन स्टूडेंट्स ने पहले अपने स्कूल के लिए अप्लाई किया था, उन्हें अब बेसिक एजुकेशन अथॉरिटीज़ में ऑनलाइन प्रेजेन्स की वजह से एक्सेप्शन नहीं माना जाएगा। इससे वर्चुअल ट्रेकिंग के ज़रिए स्टूडेंट्स के बीच स्कूल सेफ्टी के मामलों पर ज़्यादा फोकस हुआ है। अथॉरिटीज़ स्टूडेंट्स के जाने के बारे में पेरेंट्स से बातचीत करेंगी और स्कूल मैनेजमेंट के तरीकों को बेहतर बनाने के साथ-साथ री-एनरोलमेंट के मौकों पर भी विचार करेंगी।

### भूमिका:

RTE एक्ट के तहत, कम इनकम वाले परिवारों के 1,300 से ज़्यादा बच्चों को ज़िले के करीब 335 प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिया गया है। पहले भी ऐसे दावे किए गए हैं कि प्राइवेट स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर नए एडमिशन पाने के लिए खाली सीटें दिखाकर बच्चों को एडमिशन से रोकने की कोशिश करते हैं। सरकार के बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, अमित राय ने RTE स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फ़ॉलो करने का फ़ैसला किया है। स्कूल चलाने वालों से कहा गया है कि वे ड्रॉपआउट स्टूडेंट की जानकारी ऑनलाइन दें। स्टूडेंट के स्कूल छोड़ने की वजह का पता लगाने के लिए, किसी भी तरह की गड़बड़ी की जांच की जाएगी। अगर स्कूल की गलती पाई जाती है तो इसके नतीजे भुगतने होंगे। सरकार ने



ऐसे मामलों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं ताकि कम इनकम वाले ग्रुप के स्टूडेंट्स के साथ कोई नाइंसाफी न हो। ग्रेड 1 से 5 तक की प्राइमरी एजुकेशन बच्चों के आम विकास और भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। सीखने के साथ-साथ, इसमें पर्सनल, सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक काबिलियत का विकास भी शामिल है। गाज़ीपुर मुख्य रूप से एक ग्रामीण ज़िला है, और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। पहुँच और एजुकेशनल क्वालिटी पर ज़िले के कई एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशियो-इकोनॉमिक मुद्दों का असर पड़ता है। ग्रामीण इलाकों में कई सरकारी एलिमेंट्री स्कूल हैं।

### नामांकन दर और ड्रॉप-आउट

गाज़ीपुर एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट प्राइमरी एजुकेशन को एक ज़रूरी कैटेगरी के तौर पर लिस्ट करती है। सरकारी डेटा के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के 1,33,035 सरकारी प्राइमरी (क्लास 5 तक), अपर प्राइमरी (क्लास 5-8), और कम्पोजिट स्कूलों (क्लास 1-8) में एनरोल हुए स्टूडेंट्स की संख्या 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में 24 लाख से ज़्यादा कम हो गई। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 30 दिसंबर, 2023 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 2022-2023 सेशन के लिए इन स्कूलों में क्लास 1 से 8 तक के 1.92 करोड़ स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन की जानकारी पोस्ट की। डिपार्टमेंट को इस बात पर भी गर्व है कि इन इंस्टीट्यूशन में पिछले छह सालों में स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट में 40 लाख की बढ़ोतरी हुई है।

यूपी स्कूल एजुकेशन की डायरेक्टर जनरल कंचन वर्मा ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों से इस गिरावट के बारे में पूछा है। अधिकारियों के मुताबिक, अभी स्कूल-दर-स्कूल आंकड़ों की तुलना की जा रही है, और संबंधित हेडमास्टर्स से उनके जवाब मांगे जा रहे हैं।

डेटा के मुताबिक, प्रयागराज जिले के बेसिक एजुकेशन काउंसिल के स्कूलों में 2023-2024 सेशन में 2022-2023 के मुकाबले लगभग 69,000 कम स्टूडेंट थे। बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज के प्रवीण कुमार तिवारी के मुताबिक, उन्होंने सभी ब्लॉक एजुकेशन अधिकारियों से इस मामले पर उनकी राय मांगी है। अधिकारियों से इस मामले की जांच करने और इन संस्थानों में स्टूडेंट एनरोलमेंट में कमी का असली कारण बताने के लिए कहा गया है। पर्सनल वजह मिलने के बाद।

उत्तर प्रदेश के 1.3 लाख सरकारी स्कूलों में से 20% (27,931) से ज़्यादा स्कूलों में 50 से कम बच्चे एनरोल हैं इसमें 563 कम्पोजिट स्कूल, 5,352 अपर प्राइमरी स्कूल और 22,016 एलिमेंट्री स्कूल शामिल हैं। UDISE पोर्टल के स्टूडेंट डेटा के मुताबिक, 50 से कम एनरोल स्टूडेंट्स वाले सबसे ज़्यादा स्कूल आगरा (1,035), मैनपुरी (943), और कानपुर देहात (850) में हैं। सबसे कम एनरोल स्कूलों वाले जिले चंदौली (66), श्रावस्ती (35), और भदोही (9) हैं। लखनऊ में 303 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 50 से कम बच्चे एनरोल हैं।

स्कूल एजुकेशन की डायरेक्टर जनरल (DGSE) कंचन वर्मा ने कहा कि ये नंबर खराब हैं और इन पर ध्यान देना चाहिए, उन्होंने बताया कि कम एनरोलमेंट अच्छी क्वालिटी की शिक्षा में रुकावट है।

### गाज़ीपुर में नामांकन कम होना और स्कूल मर्जर नीति



गाजीपुर: उत्तर प्रदेश के काउंसिल स्कूलों में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या लगातार कम हो रही है। इन स्कूलों को कॉन्वेंट स्कूलों की तरह मॉडर्न बनाने के लिए सरकार तीन लाख रुपये खर्च कर रही है। इसके बावजूद स्टूडेंट्स की संख्या में कोई बदलाव नहीं आया है। इस हालात की वजह से शिक्षा विभाग के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है। जिले में 469 काउंसिल स्कूल ऐसे हैं, जिनमें पचास से कम स्टूडेंट्स हैं। अब लोकल स्कूलों को इन स्कूलों के साथ मिलाया जाएगा। इस फैसले की वजह से स्टूडेंट्स को इंटीग्रेटेड स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा और खाली स्कूलों को बाल वाटिका में बदला जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक, इन स्कूलों में तीन से छह साल के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।

डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक, गाजीपुर में 2266 काउंसिल स्कूल हैं, लेकिन उनमें से कई में एनरोलमेंट कम होने की वजह से स्टूडेंट्स की संख्या काफी कम है। 'पेरिंग ऑफ स्कूल्स' प्रोग्राम के तहत, सरकार के निर्देश पर 50 से कम स्टूडेंट्स वाले स्कूलों को मिलाया जाएगा। बेसिक एजुकेशन ऑफिसर हेमंत राव के मुताबिक, एजेंसी ने इन इंस्टीट्यूशन्स की लिस्ट बना ली है। जल्द ही सरकार को लिस्ट मिल जाएगी। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, 75 से कम स्टूडेंट्स वाले स्कूलों को ICT लैब या स्मार्ट क्लासरूम बनाने की इजाजत नहीं है। इसी क्रम में यह कदम उठाया जा रहा है।

'स्कूल चलो अभियान' डिपार्टमेंट की तरफ से पेरेंट्स को एजुकेट करने की एक कोशिश थी, लेकिन काउंसिल स्कूल में एडमिशन में बहुत कम दिलचस्पी थी। मर्जर के बाद, खाली बिल्डिंग्स को बाल वाटिका के अलावा पोषण वाटिका के तौर पर डेवलप किया जाएगा। एजुकेशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह एक्शन रिसोर्स का इस्तेमाल बेहतर बनाने और ग्रामीण इलाकों में एलिमेंट्री एजुकेशन को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि, यह कानून ग्रामीण इलाकों में पेरेंट्स के लिए कुछ प्रैक्टिकल मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। अगर उनके गांव के स्कूल को दूसरे स्कूलों के साथ मिला दिया जाता है, तो बच्चों को स्कूल आने-जाने के लिए लंबा सफर करना पड़ सकता है।

### नामांकन और ड्रॉप-आउट के कारण

एलिमेंट्री स्कूलों को बढ़ावा देने और बेहतर बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने "मिशन कायाकल्प" पहल शुरू की, जिसमें बेसिक सुविधाएं देने और स्कूल की मरम्मत करने की बात कही गई थी। राजापुर स्कूल में, इस प्लान का कोई असर नहीं हुआ है। स्ट्रक्चर ठीक नहीं किया गया है, और ज़रूरी एक्स्ट्रा सुविधाएं भी नहीं लगाई गई हैं।

गांव वालों का कहना है कि भ्रष्टाचार ने सरकारी कामों पर असर डाला है। उन्होंने कई बार अधिकारियों के सामने यह मामला उठाया है, लेकिन अभी तक कुछ खास नहीं हुआ है। हर बच्चे को पढ़ाई का बुनियादी हक है, लेकिन सिस्टम की हालत को देखते हुए, बच्चों का भविष्य खराब लगता है। यह एक बड़ा मुद्दा है जिस पर सरकार और प्रशासन को तुरंत ध्यान देने और सही एक्शन लेने की ज़रूरत है। ज्ञानपुर बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, भूपेंद्र नारायण सिंह ने कहा, "खराब स्कूलों का जल्द ही इम्पेक्शन और रिपेयर किया जाएगा।"

### राज्य और जिला स्तर पर नीतियाँ और कार्यक्रम



इसके अलावा, सरकार के मुश्किल एनरोलमेंट प्रोसेस की वजह से ग्रामीण इलाकों में स्कूल एनरोलमेंट पर असर पड़ रहा है, जिसमें DBT और बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड बनवाने की ज़रूरत शामिल है। उन्होंने इस आइडिया को 2009 के RTE एक्ट की भावना पर हमला बताया। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजीत कुमार सिंह ने एडमिनिस्ट्रेशन से मर्जर/पेरियरिंग प्रोजेक्ट पर फिर से सोचने के लिए कहा। अगर सरकार इस प्लान को रद्द नहीं करती है तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी।

जिन टॉपिक पर बात हुई उनमें टीचरों के ट्रांसफर, राज्य सरकार की स्कूलों को इंटीग्रेट करने की इच्छा और दूसरे मामले शामिल थे। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जितेंद्र कुमार यादव ने रिक्वेस्ट की कि सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट और मिनिस्टर 30 जून को सभी BRC पर उन स्कूलों के हेडमास्टर, SMC मेंबर, गांव के मुखिया और लोकल अधिकारियों से मिलें जहां स्टूडेंट्स की कमी है।

किताबों, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और बैग के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए तुरंत पेमेंट।

### ड्रॉप-आउट के समाधान

बहुत कम इनकम वाले परिवारों को अटेंडेंस-लिंकड इंसेंटिव के ज़रिए एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है, अगर उनकी महीने या तिमाही में अटेंडेंस 75% से ज्यादा हो। बाल मजदूरी में हिस्सा लेने का दबाव कम करने के लिए, MNREGA और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवारों के बच्चे "एजुकेशन सिक्योरिटी अलाउंस" के लिए एलिजिबल हैं। पंचायत लेवल की बाल मजदूरी मॉनिटरिंग कमेटियां (टीचर, मुखिया, आंगनवाड़ी वर्कर, ASHA, वॉलंटियर) उन बच्चों की लिस्ट बनाएं जो खतरे में हैं। आसपास के बाजारों, ईट भट्टों या खेतों में काम करने वाले बच्चों को ढूँढ़ें, उन्हें फिर से एनरोल करें और उन्हें काउंसलिंग दें। उत्तर प्रदेश का गाज़ीपुर ज़िला ज्यादातर गांव का है, जहाँ की एक बड़ी आबादी दिहाड़ी और खेती पर निर्भर है। प्राइमरी स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस (ग्रेड 1-5) बढ़ाने और ड्रॉपआउट रेट कम करने के लिए राज्य स्तर पर कई कोशिशों के बावजूद, लोकल लेवल पर अभी भी दिक्कतें हैं। समस्या के हिसाब से, अलग-अलग और लोकल लेवल पर हल नीचे दिए गए हैं।

### निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले में, जहाँ पढ़ाई का माहौल गाँव जैसा है, प्राइमरी स्कूल में एडमिशन और ड्रॉपआउट का मुद्दा पेचीदा और कई तरह का है। इन मुद्दों पर समाज के नियमों, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों, एडमिनिस्ट्रेटिव मुश्किलों, पॉलिसी चुनने और आर्थिक सीमाओं का असर पड़ता है। हालाँकि कुछ अच्छे संकेत हैं, जैसे ड्रॉपआउट रेट में कमी और राज्य स्तर की पहल से मिला डेटा, फिर भी लोकल लेवल पर सुधार लाने के लिए लगातार काम करने की ज़रूरत है। आम तौर पर, गाज़ीपुर जैसे ज़िलों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि सभी बच्चों को अच्छी क्वालिटी की, सुरक्षित और दिलचस्प शिक्षा मिले।

### संदर्भ (References)

- मेहता, अरुण सी. उत्तर प्रदेश में स्कूली शिक्षा: हम कहाँ खड़े हैं (यूडीआईएसई+ 2021-22 से 2024-25)। भारत में सभी के लिए शिक्षा, 2026।



- त्रिपाठी, रामशंकर. *भारतीय शिक्षा व्यवस्था*. नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन, 2018।
- सिंह, आर. पी. “प्राथमिक शिक्षा में ड्रॉप-आउट की समस्या.” *समाज विज्ञान शोध पत्रिका*, खंड 12, अंक 2, 2020, पृ. 45–52।
- पांडेय, शैलेन्द्र. *भारत में प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियाँ*. इलाहाबाद: लोकभारती प्रकाशन, 2017।
- कुमार, अनिल. “उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियाँ.” *शैक्षिक चिंतन पत्रिका*, खंड 8, अंक 1, 2021, पृ. 25-34।
- आज़ाद, अशोक कुमार. “ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय त्याग (ड्रॉप-आउट) की समस्या.” *समाज विज्ञान समीक्षा*, खंड 15, अंक 1, 2019, पृ. 60-68।